



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 360] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 24, 2018/आश्विन 2, 1940  
No. 360] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 24, 2018/ASHVIN 2, 1940

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2018

सं. 301-20/2018-एफएंडईए.— भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खण्ड (बी) उप-खण्ड (i) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में अगला संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित आदेश देता है, नामतः

## दूरसंचार टैरिफ (चौसठवां संशोधन) आदेश, 2018 2018 का 02

- (1) इस आदेश को दूरसंचार टैरिफ (चौसठवां संशोधन) आदेश, 2018 कहा जाएगा।  
(2) यह आदेश, सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगा।
- दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 (इसमें आगे जिसे मूल टैरिफ आदेश कहा गया है) के खंड 2 में, उपखंड (1d) और उपखंड (1e) को हटाया जाएगा।
- दूरसंचार टैरिफ आदेश के खंड 5 में, “विशेष दूरसंचार सेवा” शब्द के बाद, “प्रासंगिक मानक पैकेज में निर्दिष्ट अनुसार” शब्द हटा दिए जाएंगे।
- मूल टैरिफ आदेश के खंड 11 के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, नामतः:  
“11. सेवाओं के नियम एवं शर्तें: सेवा पैरामीटरों की गुणवत्ता के संबंध में प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट टैरिफ, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनियम अधिसूचित करके तय किए जाएंगे और सेवा प्रदाता, उपभोक्ताओं को दूरसंचार सेवाएं मुहैया कराने के नियम एवं शर्तों से अवगत कराएंगे जो किसी भी तरीके से इस आदेश और अन्य विनियमों या निदेशों, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं, के प्रावधानों के असंगत नहीं होंगे।”
- मूल टैरिफ आदेश की अनुसूची-I में—  
(क) मद (9) के लिए निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी:

मद	टैरिफ
(9) लोकल लूप टेक्नोलॉजी (फिक्स्ड) में वायरलेस सहित फिक्स्ड लाइन टेलीफोनी सेवा में ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क कॉल्स (फिक्सड)	बिलिंग चक्र का 50 मीटर्ड कॉल यूनिट्स प्रतिमाह

(ख) मद (9क) को हटाया जाएगा;

6 मूल टैरिफ आदेश के अनुसूची II में –

(क) मद (2) को हटाया जाएगा;

(ख) मद (4) के लिए, इससे संबंधित निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः—

मद	टैरिफ
(4) एक्टीवेशन प्रभार	सेवा प्रदाता द्वारा एकबारगी एक्टीवेशन चार्ज केवल तब लिया जाएगा जब ग्राहक प्रारम्भ में सेवा प्रदाता के नेटवर्क से जुड़ता है। जब ग्राहक एक टैरिफ प्लान से दूसरे टैरिफ प्लान में जाता है तो उससे दुबारा एक्टीवेशन चार्ज नहीं लिया जाएगा।

7. मूल टैरिफ आदेश में –

(क) अनुसूची III और उसके तहत प्रविष्टियां;

(ख) अनुसूची VII और उसके तहत प्रविष्टियां;

(ग) अनुसूची VIII और उसके तहत प्रविष्टियां;

(घ) अनुसूची XI और उसके तहत प्रविष्टियां;

को हटा दिया जाएगा

**टिप्पणी 1** –दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 दिनांक 09 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या 99/3 के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित किया गया था, तत्पश्चात इसमें निम्नानुसार संशोधन किए गए:

संशोधन संख्या	अधिसूचना संख्या और तारीख
पहला	301-4/99-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30.3.1999
दूसरा	301-4/99-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 31.5.1999
तीसरा	301-4/99-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 31.5.1999
चौथा	301-4/99-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 28.7.1999
5वां	301-4/99-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 17.9.1999
6वां	301-4/99-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30.9.1999
7वां	301-8/2000-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30.3.2000
8वां	301-8/2000-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 31.7.2000
9वां	301-8/2000-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 28.8.2000
10वां	306-1/99-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 9.11.2000
11वां	310-1(5)/ट्राई-2000 दिनांक 25.1.2001
12वां	301-9/2000-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 25.1.2001
13वां	303-4/ट्राई-2001 दिनांक 1.5.2001
14वां	306-2/ट्राई-2001 दिनांक 24.5.2001
15वां	310-1(5)/ट्राई-2000 दिनांक 20.7.2001
16वां	310-5(17)/2001-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 14.8.2001
17वां	301/2/2002-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 22.1.2002
18वां	303/3/2002-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30.1.2002
19वां	303/3/2002-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 28.2.2002
20वां	312-7/2001-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 14.3.2002
21वां	301-6/2002-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 13.6.2002
22वां	312-5/2002-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 4.7.2002
23वां	303/8/2002-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 6.9.2002
24वां	306-2/2003-आर्थिक दिनांक 24.1.2003
25वां	306-2/2003-आर्थिक दिनांक 12.3.2003
26वां	306-2/2003-आर्थिक दिनांक 27.3.2003
27वां	303/6/2003-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 25.4.2003
28वां	301-51/2003-आर्थिक दिनांक 5.11.2003

29वां	301-56 / 2003-आर्थिक दिनांक 3.12.2003
30वां	301-4 / 2004 (आर्थिक) दिनांक 16.1.2004
31वां	301-2 / 2004-आर्थिक दिनांक 7.7.2004
32वां	301-37 / 2004-आर्थिक दिनांक 7.10.2004
33वां	301-31 / 2004-आर्थिक दिनांक 8.12.2004
34वां	310-3(1) / 2003-आर्थिक दिनांक 11.3.2005
35वां	310-3(1) / 2003-आर्थिक दिनांक 31.3.2005
36वां	312-7 / 2003-आर्थिक दिनांक 21.4.2005
37वां	312-7 / 2003-आर्थिक दिनांक 2.5.2005
38वां	312-7 / 2003-आर्थिक दिनांक 2.6.2005
39वां	310-3(1) / 2003-आर्थिक दिनांक 8.9.2005
40वां	310-3(1) / 2003-आर्थिक दिनांक 16.9.2005
41वां	310-3(1) / 2003-आर्थिक दिनांक 29.11.2005
42वां	301-34 / 2005-आर्थिक दिनांक 7.3.2006
43वां	301-2 / 2006-आर्थिक दिनांक 21.3.2006
44वां	301-34 / 2006-आर्थिक दिनांक 24.1.2007
45वां	301-18 / 2007-आर्थिक दिनांक 5.6.2007
46वां	301-36 / 2007-आर्थिक दिनांक 24.1.2008
47वां	301-14 / 2008-आर्थिक दिनांक 17.3.2008
48वां	301-31 / 2007-आर्थिक दिनांक 01.9.2008
49वां	301-25 / 2009-ईआर दिनांक 20.11.2009
50वां	301-24 / 2012-ईआर दिनांक 19.04.2012
51वां	301-26 / 2011-ईआर दिनांक 19.04.2012
52वां	301-41 / 2012-एफएण्डईए दिनांक 19.09.2012
53वां	301-39 / 2012-एफएण्डईए दिनांक 01.10.2012
54वां	301-59 / 2012-एफएण्डईए दिनांक 05.11.2012
55वां	301-10 / 2012- एफएण्डईए दिनांक 17.06.2013
56वां	301-26 / 2012-ईआर दिनांक 26.11.2013
57वां	312-2 / 2013.एफएण्डईए दिनांक 14.07.2014
58वां	312-2 / 2013. एफएण्डईए दिनांक 01.08.2014
59वां	310-5(2) / 2013.एफएण्डईए दिनांक 21.11.2014
60वां	301-16 / 2014.एफएण्डईए दिनांक 09.04.2015
61वां	301-30 / 2016.एफएण्डईए दिनांक 22.11.2016
62वां	301-30 / 2016.एफएण्डईए दिनांक 27.12.2016
63वां	312-1 / 2017.एफएण्डईए दिनांक 16.02.2018

**टिप्पणी 2** — व्याख्यात्मक ज्ञापन (एक्सप्लेनेटरी मेमोरंडम), दूरसंचार टैरिफ (चौसठवां संशोधन) आदेश, 2018 के उद्देश्यों और कारणों को स्पष्ट करता है।

#### व्याख्यात्मक ज्ञापन (एक्सप्लेनेटरी मेमोरंडम)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (इसमें आगे जिसे प्राधिकरण कहा गया है) ने निष्फल/अनावश्यक विनियमों, जिन्हें हटाया जा सकता है, की पहचान करने के लिए प्रधान सलाहकार (एनएसएल) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति में सेवा प्रदाता और उनकी एसोसिएशनों को शामिल किया गया था, जिनकी सूची नीचे दी गई है:

1 एसीटीओ	2 एयरसेल	3 एयूसपीआई	4 भारती एयरटेल लिमिटेड	5 बीएसएनएल
6 सीओएआई	7 आइडिया	8 आईएसपीआई	9 एमटीएनएल	10 आरकॉम
11 आरजेआईएल	12 टाटा कम्युनिकेशन लि.	13 टेलीनॉर	14 टीटीएसएल	15 वोडाफोन इंडिया लि.

- 2 (क) लाइसेंसिंग, (ख) क्यूओएस और (ग) टैरिफ संबंधी मुद्दों पर निष्फल/अनावश्यक विनियमों की पहचान करने के लिए समिति के सदस्यों को लेकर तीन अलग-अलग उप-समितियों का भी गठन किया गया था। उद्योग से संबंधित उप-समिति के सदस्यों ने लिखित में जानकारी प्रस्तुत की थी, जिस पर संबंधित उप-समितियों की बैठकों में विचार, चर्चा और विश्लेषण किया गया था। इन विमर्शों के आधार पर उप-समितियों ने समिति के अध्यक्ष को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी।

- 3 तीन-उपसमितियों द्वारा विनियमों को हटाने से संबंधित सिफारिशों को समिति के सभी सदस्यों को भेजा गया था। समिति की अंतिम बैठक 28 दिसंबर, 2017 को हुई थी।
- 4 समुचित विचार-विमर्श के बाद समिति ने अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत की थी। समिति की सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ दूरसंचार टैरिफ आदेश (टीटीओ) के विभिन्न प्रावधानों को हटाने, विलय करने या संशोधित करने के प्रस्ताव शामिल किए गए थे। टीटीओ से संबंधित मुद्दों पर समिति की अंतिम सिफारिशें टीटीओ 64वां संशोधन के अनुलग्नक के रूप में संलग्न हैं।
- 5 (64वां) संशोधन में शामिल किए गए मुद्दें समिति की विभिन्न बैठकों में हुई चर्चाओं और सिफारिशों के अनुरूप थे, फिर भी प्राधिकरण ने दिनांक 09.07.2018 की प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा हितधारकों की टिप्पणियों के लिए ड्राफ्ट टीटीओ जारी कर के हितधारकों से और टिप्पणियां मंगाना उचित समझा।
- 6 टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 26.07.2018 थी और प्रति-टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 06.08.2018 थी। केवल दो हितधारकों यथा-वोडाफोन इंडिया लिमिटेड और सीओएआई ने टिप्पणियां प्रस्तुत की।
- 7 सीओएआई और वोडाफोन इंडिया लिमिटेड, दोनों सामान्य रूप से 64वें संशोधन के प्रस्तावित प्रावधानों से सहमत थे। बहरहाल, उन्होंने संबंधित मुद्दों पर कई अन्य सुझावों पर प्राधिकरण का ध्यान आकर्षित किया है जैसे:
- (i) न्यूनतम टैरिफ संरक्षण की छह माह की अवधि को घटाकर तीन माह किया जाए।
  - (ii) थोक ग्राहकों के संदर्भ में तिमाही टैरिफ अनुपालन को हटाया जाए या इसे वार्षिक भादूविप्रा अनुपालनों का हिस्सा बनाया जाए।
  - (iii) राष्ट्रीय रोमिंग टैरिफ के लिए निर्दिष्ट टैरिफ उच्चतम सीमा को समाप्त किया जाए या इसे बाजार की शक्तियों के लिए छोड़ दिया जाए।
  - (iv) हर छह माह के बाद राष्ट्रीय और देशी भाषा के समाचारपत्रों में टैरिफ सूचना के प्रकाशन की शर्त को हटाया जाए।
  - (v) एसटीवी और कंबो वाउचर्स के लिए दस और दस के गुणकों के मूल्यवर्ग का उपयोग करने का लचीलापन, टॉक टाइम वाउचर के अतिरिक्त हो।
  - (vi) टॉक टाइम वाउचर पर प्रोसेसिंग शुल्क हटाया जाए।
  - (vii) पोस्ट पेड बिलिंग के लिए हार्ड कॉपी के स्थान पर एम-बिल या ई-बिल को डिफॉल्ट विकल्प के रूप में माना जाए।
  - (viii) डीएलसी टैरिफ उच्चतम सीमा को हटाया जाए और टैरिफ निर्धारण को बाजार शक्तियों पर छोड़ा जाए।
  - (ix) विनियम 14 के तहत पंजीकृत टेलीमार्केटर या लेनदेन संबंधी संदेश भेजने वाली संस्था के अलावा व्यक्तियों द्वारा भेजे गए 50 पैसा/शॉर्ट मैसेज सर्विसेज (एसएमएस) के आधार मूल्य को हटाया जाना चाहिए।
- 8 प्राधिकरण ने सीओएआई और वोडाफोन द्वारा मुहैया कराई गई टिप्पणियों पर विचार किया और निष्फल विनियमों के हटाने के लिए गठित समिति व उपसमिति की कई बैठकों के दौरान किए गए विचार विमर्श पर करीब से पर्यवेक्षण किया और यह पाया गया कि उपरोक्त सभी मुद्दें समिति के सदस्यों के साथ बैठक में उठाए गए थे और इन पर विचार किया गया था, जिसमें अन्य के साथ-साथ सीओएआई और वोडाफोन, दोनों के प्रतिनिधि शामिल थे। समिति की अंतिम सिफारिशों से निष्कर्ष जो इस टीटीओ से जुड़ा हुआ है विभिन्न मुद्दों और उसके कारणों पर किए गए निर्णयों की सूची देता है। इस टीटीओ का उद्देश्य मुख्यतया समिति की सिफारिशों के अनुसार टीटीओ के विभिन्न निष्फल और अनावश्यक प्रावधानों को हटाना, संशोधित या विलय करना है। किसी वर्तमान टैरिफ उच्चतम सीमा की समीक्षा करने, विनियमन या निर्देश देने से संबंधित अन्य सुझावों पर अलग से विचार किया जा सकता है, जैसा कि समिति ने सिफारिश की है।
- 9 टिप्पणियों में दिए गए एक विशिष्ट सुझाव के अनुसार यह स्पष्ट करना है कि प्रतिभूति जमा पर उच्चतम सीमा, जो 12 माह के किराये से अधिक नहीं है, को अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग और आईएसडी पर लागू न किया जाए। प्राधिकरण इस सुझाव से सहमत है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस टीटीओ के खंड 5 में उल्लिखित प्रतिभूति जमा पर लागू उच्चतम सीमा को आईएसडी और अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग सेवाओं के लिए लागू नहीं किया जाएगा।

भौलेन्द्र कुमार मिश्रा, प्रधान सलाहकार (एफएंडईए)

[विज्ञापन-III/4/असा./236/18]

## अनुलग्नक

## निष्फल विनियम शोधन समिति की रिपोर्ट – दूरसंचार टैरिफ आदेश के संबंध में

क्र.सं.	टीटीओ प्रावधान/अनुसूचियां	सिफारिश
1	<b>धारा II- परिभाषा 'Id': रोमिंग टैरिफ प्लान</b> “रोमिंग टैरिफ प्लान” या “आरटीपी” का आशय उस टैरिफ प्लान से है, जिसमें लोकल और लंबी दूरी (अंतर सर्कल), दोनों के लिए आउटगोइंग वॉइस कॉल और आउटगोइंग एसएमएस के प्रभारों में देश के अंदर उपभोक्ता की लोकेशन के साथ बदलाव नहीं होगा।	टीटीओ से इस परिभाषा को हटाया जाए क्योंकि कालांतर में संशोधित टीटीओ (60वां संशोधन) में “विशेष रोमिंग टैरिफ प्लान” की नई अवधारणा शुरू की गई थी।
2	<b>धारा II. परिभाषा 'le': रोमिंग टैरिफ प्लान-एफआर</b> “रोमिंग टैरिफ प्लान-एफआर” या आरटीपी-एफआर” का आशय ऐसे आरटीपी से है जिसमें सेवा प्रदाता द्वारा निर्धारित किया गया निश्चित प्रभार, यदि कोई हो, के भुगतान पर राष्ट्रीय रोमिंग पर इनकमिंग वॉइस कॉल के लिए कोई प्रभार नहीं लिया जाता है।	टीटीओ से इस परिभाषा को हटाया जाए क्योंकि कालांतर में संशोधित टीटीओ (60वां संशोधन) में “विशेष रोमिंग टैरिफ प्लान” की नई अवधारणा शुरू की गई थी।
3	<b>धारा III- खंड 5 : डिपॉजिट –</b> जब तक कि अन्यथा प्रावधान न हो, तब तक कोई भी सेवा प्रदाता किसी भी उपभोक्ता से संबंधित मानक पैकेज में यथा निर्दिष्ट दूरसंचार सेवा विशेष के लिए उपभोक्ता से एक वर्ष के प्रभारयोग्य किराये से अधिक किसी दूरसंचार सेवा के लिए डिपॉजिट के रूप के किसी राशि की मांग या प्राप्त नहीं करेगा।	<b>धारा III- खंड 5 : डिपॉजिट – ऐसा पढ़ा जाएगा:</b> जब तक कि अन्यथा प्रावधान न हो, तब तक कोई भी सेवा प्रदाता निर्दिष्ट दूरसंचार सेवा विशेष के लिए उपभोक्ता से एक वर्ष के प्रभारयोग्य किराये से अधिक किसी दूरसंचार सेवा के लिए डिपॉजिट के रूप के किसी राशि की मांग या प्राप्त नहीं करेगा।
4	<b>धारा IV- खंड 11: सेवाओं के नियम एवं शर्तें –</b> सेवा पैरामीटरों की गुणवत्ता के संबंध में प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट टैरिफ, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनियम अधिसूचित करके तय किए जाएं। सेवा प्रदाता उपभोक्ताओं को दूरसंचार सेवाएं मुहैया कराने के नियम एवं शर्तों के बारे स्पष्ट रूप से बताएंगे, जो किसी भी तरीके से इस आदेश के प्रावधानों के असंगत नहीं होंगे। इन नियम एवं शर्तों में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे: (क) नियम एवं शर्तें, जिनके तहत ऐसी सेवाएं प्राप्त, उपयोग, समाप्त की जाएंगी; (ख) सेवा उपयोग, बिलिंग, मरम्मत, दोष सुधार इत्यादि से संबंधित नियम एवं शर्तें; (ग) उपभोक्ता को उपलब्ध टैरिफ पैकेज तत्संबंधी शर्तों के साथ विकल्प बदलने हेतु उपलब्ध प्रक्रिया का विकल्प।	समिति ने इस तथ्य के आधार पर इस खंड की विषयवस्तु में संशोधन की सिफारिश करने की निर्णय लिया कि इसे टीटीओ के प्रारंभिक चरणों में शामिल किया गया था, जब अलग क्यूओएस विनियम नहीं थे। इस खंड के तहत उल्लिखित नियम एवं शर्तें, बाद के वर्षों में भादूविप्रा द्वारा संशोधन के बाद के क्यू ओ एस संबंधी विनियमों में शामिल किए गए हैं। टीटीओ में संशोधन करते समय इस खंड को पुनः परिभाषित किया जाएगा।
5	<b>अनुसूची 1 – बेसिक सेवाएं (आईएसडीएन से इतर)</b> मद (9): ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क कॉल (या अप्रभारित कॉल) मद (9क): लोकल लूप टेक्नोलॉजी (फिक्स्ड) में वायरलेस सहित फिक्स्ड लाइन टेलीफोनी सेवा	इन दोनों खंडों को मिलाने की सिफारिश की गई है।
6	<b>अनुसूची II- सेल्युलर मोबाइल दूरसंचार सेवा (सीएमटीएस)</b> <b>मद (2) किराया और एयरटाइम प्रभार –</b> स्थगन में प्रावधान है कि: प्रत्येक सेवा प्रदाता “सेवा प्रदाता का संदर्भ टैरिफ पैकेज” के रूप में 30 सेकंड की पल्स अवधि के साथ मासिक किराया और एयरटाइम प्रति मिनट निर्दिष्ट करेगा। किसी भी टैरिफ पैकेट अर्थात् संदर्भ/वैकल्पिक में इनकमिंग	‘संदर्भ टैरिफ पैकेज’ और ‘30 सेकंड की पल्स अवधि’ की अवधारणा अप्रासंगिक हो गई है और इस अनावश्यक अवधारणा को हटाया जाना जरूरी है। इसी प्रकार ‘एयर टाइम प्रभार’ की अवधारणा भी अनावश्यक हो गई है।

	कॉल के लिए कोई एयरटाइम प्रभार नहीं होगा।	
7	अनुसूची II- सेल्युलर मोबाइल दूरसंचार सेवा (सीएमटीएस), मद (4) संस्थापना प्रभार	(i) "संस्थापना प्रभार" को "एक्टिवेशन प्रभार" से बदला जाए। (ii) निम्नलिखित पंक्तियां हटाई जाएंगी: "सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत और कोई अप-फ्रंट भुगतान या आवर्ती प्रभार या शुल्क या ऐसी कोई राशि, चाहे जिस भी नाम या विवरण की हो, किसी भी मौजूदा लाइफ टाइम वैलिडिटी प्लान या अनलिमिटेड वैलिडिटी प्लान (इसमें आगे जिसे मौजूदा टैरिफ प्लान कहा गया है) के उपभोक्ता से नहीं ली जाएगी, बशर्ते कि ऐसा उपभोक्ता कम प्रवेश शुल्क वाले नए लाइफ टाइम वैलिडिटी या अनलिमिटेड वैलिडिटी प्लान में माइग्रेशन का विकल्प चुनता है।
8	अनुसूची II- सेल्युलर मोबाइल दूरसंचार सेवा (सीएमटीएस) मद (7क) छियालीसवा संशोधन ग्राहक को बिल की हार्ड कॉपी, बिल की प्रिंटेड कॉपी प्रदान करने हेतु टैरिफ – शून्य	इसे पुनःपरिभाषित किया जाएगा ताकि बिल की हार्ड कॉपी के लिए उपभोक्ता द्वारा "ऑफ्ट-इन" का विकल्प शुरू किया जा सके, यदि ऐसा अपेक्षित हो। (इस वि"य पर कमिटी की सिफारिशों पर अलग से परामर्श प्रक्रिया द्वारा विचार विमर्श किया जाएगा।)
9	अनुसूची III- रेडियो पेजिंग सेवाएं	अनावश्यक है, हटाया जाए
10	अनुसूची VII- मूल्य संवर्धित सेवाएं और अन्य सेवाएं, जो कहीं और निर्दिष्ट नहीं की गई हैं	अनावश्यक है, हटाया जाए
11	अनुसूची VIII- टेलेक्स और टेलीग्राफ सेवाएं	अनावश्यक है, हटाया जाए
12	अनुसूची XI- दूरसंचार अवांछित वाणिज्यिक संप्रेषण विनियम, 2007 (2007 का 4) के विनियम 16 के उपविनियम (3) के खंड (ख) में संदर्भित अवांछित वाणिज्यिक संप्रेषण के लिए टैरिफ।	निरस्त किया जाए क्योंकि टीसीसीसीपी विनियम ने पिछले यूसीसी विनियम को प्रतिस्थापित कर दिया है।

## TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2018

**No. 301-20/2018-F&EA.** — In exercise of the powers conferred upon it under sub-section (2) of section 11, read with sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (1) of the said section, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order further to amend the Telecommunication Tariff Order, 1999, namely:-

#### THE TELECOMMUNICATION TARIFF (SIXTY FOURTH AMENDMENT) ORDER, 2018

No. 02 of 2018

- This Order may be called the Telecommunication Tariff (Sixty Fourth Amendment) Order, 2018.
  - It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
- In clause 2 of the Telecommunication Tariff Order, 1999 (hereinafter referred to as the principal tariff order), sub-clause (1d) and sub-clause (1e) shall be deleted.
- In Clause 5 of the principal tariff order, after the words "the particular telecommunication service", the words "as specified in the relevant standard package" shall be deleted.
- For clause 11 of the principal tariff order the following clause shall be substituted, namely:-

"11. Terms and Conditions of services: The tariff specified by the Authority relates to quality of service parameters that may be set by the Authority through regulations notified from time to time and the service providers shall convey the terms and conditions of the provision of telecommunication services to subscribers which shall not in any manner be

inconsistent with the provisions of this Order and other regulations or directions that may be issued by the Authority from time to time.”

5. In Schedule I to the principal tariff order –

(a) For item (9), the following item and entries shall be substituted;

ITEM	TARIFF
(9) Free calls (or uncharged calls) for rural subscribers in fixed line telephony service including wireless in local loop technology (Fixed)	50 metered call units per month of a billing cycle

(b) Item (9.a) shall be deleted;

6. In Schedule II to the principal tariff order -

(a) Item (2) shall be deleted;

(b) For item (4), the following item and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

ITEM	TARIFF
(4) Activation charge	One time activation charge may be levied by a service provider only when a customer initially gets connected to the network of the service provider. No further activation charge shall be levied when a subscriber moves from one tariff plan to another.

7. In the principal tariff order -

(a) Schedule III and entries thereunder;

(b) Schedule VII and entries thereunder;

(c) Schedule VIII and entries thereunder; and

(d) Schedule XI and entries thereunder;

shall be deleted

**Note.1.** – The Telecommunication Tariff Order, 1999 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 under notification No.99/3 dated 9th March, 1999, and subsequently amended as given below:

Amendment No.	Notification No. and Date
1 <sup>st</sup>	301-4/99-TRAI (Econ) dated 30.3.1999
2 <sup>nd</sup>	301-4/99-TRAI(Econ) dated 31.5.1999
3 <sup>rd</sup>	301-4/99-TRAI(Econ) dated 31.5.1999
4 <sup>th</sup>	301-4/99-TRAI(Econ) dated 28.7.1999
5 <sup>th</sup>	301-4/99-TRAI(Econ) dated 17.9.1999
6 <sup>th</sup>	301-4/99-TRAI(Econ) dated 30.9.1999
7 <sup>th</sup>	301-8/2000-TRAI(Econ) dated 30.3.2000
8 <sup>th</sup>	301-8/2000-TRAI(Econ) dated 31.7.2000
9 <sup>th</sup>	301-8/2000-TRAI(Econ) dated 28.8.2000
10 <sup>th</sup>	306-1/99-TRAI(Econ) dated 9.11.2000
11 <sup>th</sup>	310-1(5)/TRAI-2000 dated 25.1.2001
12 <sup>th</sup>	301-9/2000-TRAI(Econ) dated 25.1.2001
13 <sup>th</sup>	303-4/TRAI-2001 dated 1.5.2001
14 <sup>th</sup>	306-2/TRAI-2001 dated 24.5.2001
15 <sup>th</sup>	310-1(5)/TRAI-2000 dated 20.7.2001
16 <sup>th</sup>	310-5(17)/2001-TRAI(Econ) dated 14.8.2001
17 <sup>th</sup>	301/2/2002-TRAI(Econ) dated 22.1.2002
18 <sup>th</sup>	303/3/2002-TRAI(Econ) dated 30.1.2002
19 <sup>th</sup>	303/3/2002-TRAI(Econ) dated 28.2.2002
20 <sup>th</sup>	312-7/2001-TRAI(Econ) 14.3.2002
21 <sup>st</sup>	301-6/2002-TRAI(Econ) dated 13.6.2002
22 <sup>nd</sup>	312-5/2002-TRAI(Eco) dated 4.7.2002

23 <sup>rd</sup>	303/8/2002-TRAI(Econ) dated 6.9.2002
24 <sup>th</sup>	306-2/2003-Econ dated 24.1.2003
25 <sup>th</sup>	306-2/2003-Econ dated 12.3.2003
26 <sup>th</sup>	306-2/2003-Econ dated 27.3.2003
27 <sup>th</sup>	303/6/2003-TRAI(Econ) dated 25.4.2003
28 <sup>th</sup>	301-51/2003-Econ dated 5.11.2003
29 <sup>th</sup>	301-56/2003-Econ dated 3.12.2003
30 <sup>th</sup>	301-4/2004(Econ) dated 16.1.2004
31 <sup>st</sup>	301-2/2004-Eco dated 7.7.2004
32 <sup>nd</sup>	301-37/2004-Eco dated 7.10.2004
33 <sup>rd</sup>	301-31/2004-Eco dated 8.12.2004
34 <sup>th</sup>	310-3(1)/2003-Eco dated 11.3.2005
35 <sup>th</sup>	310-3(1)/2003-Eco dated 31.3.2005
36 <sup>th</sup>	312-7/2003-Eco dated 21.4.2005
37 <sup>th</sup>	312-7/2003-Eco dated 2.5.2005
38 <sup>th</sup>	312-7/2003-Eco dated 2.6.2005
39 <sup>th</sup>	310-3(1)/2003-Eco dated 8.9.2005
40 <sup>th</sup>	310-3(1)/2003-Eco dated 16.9.2005
41 <sup>st</sup>	310-3(1)/2003-Eco dated 29.11.2005
42 <sup>nd</sup>	301-34/2005-Eco dated 7.3.2006
43 <sup>rd</sup>	301-2/2006-Eco dated 21.3.2006
44 <sup>th</sup>	301-34/2006-Eco dated 24.1.2007
45 <sup>th</sup>	301-18/2007-Eco dated 5.6.2007
46 <sup>th</sup>	301-36/2007-Eco dated 24.1.2008
47 <sup>th</sup>	301-14/2008-Eco dated 17.3.2008
48 <sup>th</sup>	301-31/2007-Eco dated 1.9.2008
49 <sup>th</sup>	301-25/2009-ER dated 20.11.2009
50 <sup>th</sup>	301-24/2012-ER dated 19.4.2012
51 <sup>st</sup>	301-26/2011-ER dated 19.4.2012
52 <sup>nd</sup>	301-41/2012-F&EA dated 19.09.2012
53 <sup>rd</sup>	301-39/2012-F&EA dated 1.10.2012
54 <sup>th</sup>	301-59/2012-F&EA dated 05.11.2012
55 <sup>th</sup>	301-10/2012-F&EA dated 17.06.2013
56 <sup>th</sup>	301-26/2012-ER dated 26.11.2013
57 <sup>th</sup>	312-2/2013-F&EA dated 14.07.2014
58 <sup>th</sup>	312-2/2013- F&EA dated 01.08.2014
59 <sup>th</sup>	310-5 (2)/2013-F&EA dated 21.11.2014
60 <sup>th</sup>	301-16/2014-F&EA dated 09.04.2015
61 <sup>st</sup>	301-30/2016-F&EA dated 22.11.2016
62 <sup>nd</sup>	301-30/2016-F&EA dated 27.12.2016
63 <sup>rd</sup>	312-1/2017-F&EA dated 16.02.2018

**Note.2.** – The Explanatory Memorandum explains the reason for the Telecommunication Tariff (Sixty Forth Amendment) Order, 2018.

### EXPLANATORY MEMORANDUM

Telecom Regulatory Authority of India (hereby referred to as the Authority) had constituted a Committee under the Chairmanship of Principal Advisor (NSL) to identify infructuous/ redundant regulations which could be purged. The Committee comprised of service providers and their associations as listed below:

1. ACTO	2. Aircel	3. AUSPI	4. Bharti Airtel Ltd.	5. BSNL
6. COAI	7. Idea	8. ISPAI	9. MTNL	10. Rcom
11. RJIL	12. Tata Communication Ltd.	13. Telenor	14. TTSL	15. Vodafone India Ltd.

2. Three separate sub-committees were also formed from amongst the members of the Committee to identify infructuous/ redundant regulations on (a) licensing, (b) QoS, and (c) tariff related issues. The sub-committee members from the industry had submitted written inputs which were considered, discussed and analysed in the meetings of



respective sub-committees. Based on such deliberations, the sub-committees had submitted their recommendations to the Chairperson of the Committee.

3. The recommendations regarding purging of regulations made by the three sub-committees were circulated to all the members of the Committee. The final meeting of the Committee was held on 28th December 2017.

4. After due deliberations, the Committee has submitted final recommendations. The recommendations of the Committee, inter alia, include proposals to delete, merge, or modify various provisions of the Telecommunication Tariff Order (TTO). The final recommendations of the Committee on issues related to TTO are placed as Annexure to the TTO 64th Amendment.

5. Even though the issues covered in the TTO (64th) Amendment were in line with the deliberations and recommendations in various committee meetings, the Authority considered it appropriate to seek further views of stakeholders by releasing the draft TTO seeking comments of stakeholders vide Press Release dated 09.07.2018.

6. The last date to receive comments was 26.07.2018 and the last date to receive counter comments was 06.08.2018. Only two stakeholders namely Vodafone India Limited and COAI have submitted comments.

7. Both COAI and Vodafone India Limited were generally in agreement with the proposed provisions of 64th Amendment. However, they have invited attention of the Authority to several other suggestions on related issues such as:

- (i) Minimum tariff protection of six months should be changed to three months.
- (ii) Quarterly tariff compliance w.r.t bulk customers should be done away with/ or should be made a part of yearly TRAI compliances.
- (iii) Tariff Ceilings specified for National Roaming tariffs should be abolished and should be left to market forces.
- (iv) Publication of tariff information in national and vernacular language newspaper after every six months should be removed.
- (v) Flexibility to use the denomination of Rupees Ten and multiples thereof for STVs and Combo vouchers also in addition to Top up voucher.
- (vi) Processing fee on Top up voucher should be removed.
- (vii) M-bill or e-bill should be considered as default option for post-paid billing replacing of hard copy
- (viii) DLC tariff ceiling should be removed and let market forces to decide the tariffs.
- (ix) Floor price of 50p/Short Message Services (SMS) sent by persons other than a telemarketer registered under regulation 14 or an entity sending transactional message should be removed.

8. The Authority considered the comments provided by COAI and Vodafone and also closely looked at the deliberations made during several meetings of the committee and that of the sub-committee on tariff set up for purging infructuous regulations. It was found that the above issues were raised and deliberated upon during the meeting with members of the committee which, inter alia, included representatives from both COAI and Vodafone. Extracts from the final recommendations of the committee which is annexed to this TTO lists the decisions taken on various issues and the rationale thereof. The purpose of this TTO is basically to delete, modify or merge various infructuous provisions of TTO as per the recommendations of the committee. Other suggestions for reviewing any existing tariff ceiling, regulation or direction can be considered separately as recommended by the committee.

9. One specific suggestion made in the comments on the draft TTO 64th Amendment is to explicitly clarify that the ceiling on security deposit which is not more than 12 months rental should not be made applicable to International Roaming and ISD. The Authority is in agreement with this suggestion. It is hereby clarified that the ceiling on Security deposit mentioned in clause 5 of the principal tariff order will not be applicable for ISD and International Roaming Services.

S.K. MISHRA, Pricipal Advisor (F&EA),

[ADVT.-III/4/Exty./236/18]

## Annexure

## Extracts from Report of the Committee for Purging of Infructuous Regulations- Regarding Telecommunication Tariff Order

S. NO.	TTO Provisions/ Schedules	Recommendation
1	<b>Section II- Definition 'Id': Roaming Tariff Plan</b> Roaming Tariff Plan" or "RTP" means a tariff plan in which the charges for outgoing voice calls and outgoing SMS, both local as well as long distance (inter-circle), shall not change with the location of the subscriber within the country.	To delete this definition from the TTO, since subsequently amended TTO (60 <sup>th</sup> Amendment) had introduced the new concept of "special Roaming Tariff plan".
2	<b>Section II- Definition 'le': Roaming Tariff Plan-FR</b> "Roaming Tariff Plan-FR" or "RTP-FR" means an RTP in which there is no charge for incoming voice calls while on national roaming, on payment of fixed charge, if any, as may be determined by the service provider.	To delete this definition from the TTO, since subsequently amended TTO (60 <sup>th</sup> Amendment) had introduced the new concept of "special Roaming Tariff plan".
3	<b>Section III- Clause 5 : Deposits –</b>  Unless otherwise provided for, no service provider shall seek or obtain from any subscriber in any form any amount as deposit for any telecommunication service in excess of one year's rental chargeable from the subscriber for the particular telecommunication service as specified in the relevant standard package.	<b>Section III- Clause 5 : Deposits – shall read as :</b>  Unless otherwise provided for, no service provider shall seek or obtain from any subscriber in any form any amount as deposit for any telecommunication service in excess of one year's rental chargeable from the subscriber for the particular telecommunication service.
4	<b>Section IV- Clause 11: Terms and Conditions of Services-</b>  The tariff specified by the Authority relates to quality of service parameters that may be set by the Authority from time to time. Service Providers shall clearly indicate the terms and conditions of the provision of telecommunication services to subscribers which shall not in any manner be inconsistent with the provisions of this Order. Such terms and conditions shall, <i>inter-alia</i> , include the following:  (a) Terms and conditions under which such services may be obtained, utilized and terminated; (b) Terms and conditions relating to the use of service, billing, repair, fault rectification and the like; (c) Choice of the tariff packages available to a subscriber and procedure available for revising the choice along with the conditions thereof.	The committee decided to recommend modification of the content of this clause considering the fact that this was incorporated in the initial stages of TTO when there were no separate QoS regulations. The terms and conditions mentioned under this clause are covered by subsequent QoS related regulations modified by TRAI in subsequent years.  The re-wording of this clause will be done while revising the TTO.
5	<b>Schedule 1- Basic Services (Other than ISDN)</b>  Item (9): Free calls (or uncharged calls) for rural subscribers  Item (9.a): Fixed line telephony service including wireless in local loop technology (Fixed)	Recommended to merge the two clauses.
6	<b>Schedule II- Cellular Mobile Telecom Service (CMTS),</b> <b>Item (2) Rental and airtime charge-</b> Forbearance provided that:  Every service provider shall specify a monthly rental and airtime charge per minute with a pulse duration of 30 seconds, as a "Reference Tariff Package of the Service Provider". No airtime charge for incoming calls in any of the tariff package i.e. Reference/ Alternative.	The concept of 'Reference Tariff Package' and 'pulse duration of 30 seconds' have become irrelevant and are required to be removed being infructuous.  Similarly the concept of 'air time charge' has also become infructuous.
7	<b>Schedule II- Cellular Mobile Telecom Service (CMTS),</b>	(i)"Installation Charges" to be substituted with "Activation Charges"

	<b>Item (4) Installation Charges</b>	(ii) Following Lines were to be deleted: <i>“offered by a service provider and no up-front payment or recurring charges or fee or any such amount by whatever name or description, shall be levied from a subscriber of any existing life-time validity plan or unlimited validity plan (hereafter referred to as existing tariff plan) if such subscriber opts for migration to a new life-time validity or unlimited validity plan with lower entry fee”</i>
8	<b>Schedule II- Cellular Mobile Telecom Service (CMTS),</b> Item (7A)- Forty Sixth Amendment Tariff for provision of hard copy of the bill or printed copy of the bill to the customer– <b>Nil</b>	To be re-worded, so as to introduce option “opt-in” by the subscriber for hard copy of the bill, if so required. (This recommendation of the Committee is being deliberated through a separate consultation process.)
9	Schedule III- Radio Paging Services	Redundant , to be deleted
10	Schedule VII- Value Added Services and Other Services not elsewhere specified	Redundant , to be deleted
11	Schedule VIII- Telex and Telegraph Services	Redundant , to be deleted
12	Schedule XI- Tariff for Unsolicited commercial communication referred to in clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 16 of the Telecom Unsolicited Commercial Communications Regulations, 2007 (4 of 2007).	To be repealed as the TCCCP Regulation has replaced the earlier UCC Regulation